

Title: Urged that the Minister of Parliamentary Affairs may direct the Minister of Rural Development to ask for a report from the Government of Uttar Pradesh regarding alleged diversion and misuse of money given under the Prime Minister's Gramin Sadak Yojana.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत एक हजार तक की आबादी के गांवों को वर्ष 2003 तक सड़क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है और पांच सौ तक की आबादी के गांवों को वर्ष 2007 तक पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत धन भी आबंटित कर दिया है। इसी सदन में पिछले सत्र में जब बहुत से सांसदों ने तो ग्रामीण विकास मंत्री श्री वेंकैयानायडू जी से शिकायत की थी कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत

* Not Recorded

निर्धारित मानक के अनुरूप राज्य सरकारें काम नहीं कर रही हैं तो उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि हम सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर इस संदर्भ में आये गतिरोध को दूर करेंगे। हम सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी तक श्री वेंकैयानायडू, ग्रामीण विकास मंत्री ने अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया है। मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जो धन आबंटित किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उस धन का दुरुपयोग किया है, उस धन को दूसरी मदों में डाइवर्ट करने का काम किया है। हम सदन के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से मांग करते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री श्री वेंकैयानायडू जी को निर्देशित करें कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मंगाकर पूछें कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत उन्होंने किन-किन जगहों पर कितना धन खर्च किया है। मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत आज की तारीख में एक इंच भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। **वै। (ब्यवधान)** उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना के धन का राजनैतिक उद्देश्य के लिये उपयोग करना चाहती है।